भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1212

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979

1212. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 का देश भर में, विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में, प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में कामगारों को तैनात करने वाले कई ठेकेदार उनका पंजीकरण नहीं करा रहे हैं और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक परियोजनाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों में, अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे दोषी ठेकेदारों और नियोक्ताओं के विरूद्ध कठोर निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का विचार है जो अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों का पंजीकरण करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहते हैं; और

(ङ) सरकारी प्रतिष्ठानों में पिछले तीन वर्षों में उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): प्रवासी कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए संसद ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान करता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएँ और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किए जाने अपेक्षित होते हैं।

जारी-2/-

केंद्रीय औद्योगिक संबंध कार्यतंत्र (सीआईआरएम) के अंतर्गत प्रवर्तन प्राधिकारी केंद्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में अधिनियम को प्रवर्तित करने का अधिदेश दिया गया है।

श्रम सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया है, ताकि यादृच्छिक जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली के साथ-साथ व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान करते हुए अनुपालन को सुगम बनाया जा सके, जिससे कानून कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए व्यक्तिपरकता कम हो गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कामगारों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों द्वारा औद्योगिक विवाद दायर करने की सुविधा के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। इसमें उपदान संदाय अधिनियम, 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कामगारों द्वारा दावा-मामले दायर करने की सुविधा भी है।

****